मोहम्मद. असलम @ भूरे बनाम भारत संघ और अन्य

31 मार्च 2003

[एस. राजेंद्र बाबू, सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी, एम.बी. शाह, एन. संतोष हेगड़े और दोराईस्वामी राजू, न्यायमूर्तिगण]

जनहित याचिका:

अयोध्या में निश्चित क्षेत्र का अधिग्रहण अधिनियम, 1993–अयोध्या भूमि–विवाद–तत्कालीन रामजन्म भूमि–बाबरी मस्जिद संरचना से संबंधित– 1993 अधिनियम के बाद के अधिनियमन–उच्च न्यायालय के समक्ष शीर्षक मुकदमे–लंबित– निकटवर्ती भूमि के संरक्षण की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट याचिका मालिकाना हक के मुकदमों में अंतिम निर्णय – यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया धार्मिक गतिविधि पर रोक–रिट याचिका का निपटारा–हेल्ड: स्थिति एक दशक से अधिक समय से यथास्थिति कायम है और टाइटल सूट हाई के समक्ष लंबित है अदालतें अंतिम चरण में पहुंच रही हैं, और संपत्ति को उसके मूल रूप में संरक्षित भी किया जा रहा है स्थिति अत्यंत आवश्यक है, स्थिति को बिगाड़ना उचित नहीं है मामले–इस प्रकार अंतरिम आदेश उच्च न्यायालय में स्वामित्व मुकदमों के निपटान तक प्रभावी रहेगा

लंबे समय से एयोध्या में पूर्वकालीन राम जन्म भूमि–बाबरी मस्जिद संरचना के संबंध में एक सांप्रदायिक विवाद रहा है। इसके परिणामस्वरूप, एक्यूइजिशन ऑफ सर्टन एरिया एट एयोध्या एक्ट, 1993 का अधिनमन किया गया। इसका उद्देश्य देश में विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखना और सार्वजनिक आदर्श को बनाए रखना था, जिसके लिए एयोध्या में कुछ क्षेत्रों को अधिग्रहण करने की आवश्यकता थी। इसके बाद, दावेदारों ने विवादित और समान्य भूमि के मालिकाना दावा करने वाले शीर्षक मुकदमे दर्ज किया। प्रार्थी फिर इस सार्वजनिक हित पीटीशन को दर्ज कराया, जिसमें शीर्षक मुकदमे के अंतिम निर्णय तक पास भूमि की संरक्षण की मांग की गई थी। इस महकमे ने फिर विभिन्न धाराओं के अंतरिम आदेश की निरसन करने और पीटीशन के अंतिम सुनवाई की मांग करने के लिए एक आवेदन दर्ज किया। प्रार्थी ने दावा किया कि इस महकमे के म. इस्माइल फारूकी के मामले में दिए गए निर्णय से स्पष्ट रूप से प्रशासन बनाने के लिए आस–पास की भूमि की सहायकता की जानी चाहिए, जिसके मालिक को उच्च न्यायालय द्वारा आखिरकार घोषित किया जाने है, और इस महकमे द्वारा दिए गए विचारों के परीक्षण के साथ साथ यह महकमा अधिग्रहण किए जाने वाले क्षेत्र के लिए आवश्यक विकसन की योजना के संदर्भ में उपयोग किए जाने वाले देखभाल की जाने चाहिए, जिसके लिए उच्च न्यायालय के समक्ष पेंडिंग मुकदमों के निर्णय की जाना चाहिए, इसलिए अंतरिम आदेश में पारिपरिणामिक किया जाना चाहिए और एक उपयुक्त राहत प्रदान की जानी चाहिए।

उत्तरदाता ने विरोध किया कि इस महकमे द्वारा पहले दिए गए अंतरिम राहत महकमे के निर्णय के दायरे के बाहर जाते हैं और इस महकमे द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश में म. इस्माइल फारूकी के मामले में इस महकमे द्वारा दिए गए निर्णय के लिए किसी भी उत्तराधिकार की स्थापना के लिए कोई उचित आधार नहीं है और इसलिए पीटीशन को सीधे खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उसने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट पीटीशन दायर की थी जो खारिज की गई थी और इस पीटीशन में किसी भी राहत को प्रदान करने के लिए कोई उचित आधार किया गया है; और इसमें किए गए आरोप अस्पष्ट हैं और विचारों को समझने के लिए आवश्यक विवरण शामिल नहीं हैं और पीटीशन में कई दरियाफ्त पहले ही अस्थित हो गई हैं।

इस प्रादेश याचिका को निस्स्तरित करते हुए, इस न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: I. I. उपस्थित भूमि, हालांकि केंद्र सरकार में है, विवादित संपत्ति के संबंध में महकमे में पेंडिंग विवाद के परिणामों के आधार पर विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जाना होगा। जमीन की अधिग्रहण का अधिग्रहण मुख उद्देश्य के लिए आंशिक है। इस प्रकार, दो प्राप्त जमीनें एक–दूसरे के साथ आंतरिक रूप से जुड़ी हुई हैं और प्रक्रिया के इस चरण में उन्हें भिन्न व्यवहार के लिए अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरे, यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई भूमि अत्यधिक हो जाती है, तो ऐसी भूमि को उस मालिक को वापस करनी होगी जिसे अधिग्रहण की वैधता को चुनौती देने के लिए उचित प्रक्रिया शुरू करनी हो सकती है। इस चरण में किसी अन्य निकाय या ट्रस्ट को जैसे कि एक्यूइजिशन ऑफ सर्टन एरिया एट अयोध्या एक्ट, 1993 के अनुच्छेद 6 के तहत प्रदान किया गया है, तो इस चरण में और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए, मामले अंत में निर्णय दिया जाने तक स्थिति का दिर्दर्शन बनाए रखना होगा। इस महकमे द्वारा पहले दिए गए आदेश ने इस को बाह्य नहीं किया है कि अधिग्रहण औचित रूप से विवादित भूमि के मालिक के द्वारा उसकी सही उपभोग की सुविधा की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य के रूप में है। [154– सी.एफ.]

1.2. स्थिति को 1992 के बाद से बनाए रखी गई है और अब तक विष्णुधर्मों के किए जाने वाले तबादले की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। जब बहुत दिनों से एक विशेष स्थिति बनी हुई है – जैसे कि इस मामले में अब तक दशकों के लिए – और जब उच्च न्यायालय में पेंडिंग विवाद की निर्णयप्राप्तिमें हैं, और यह भी पूरी तरह से जाना जाता है कि संपत्ति की सजीव स्थिति को बनाए रखना बिल्कुल आवश्यक है ताकि महकमों के प्रमाणांकन के बाद पार्टियों को उचित राहत दी जा सके, तो इस स्थिति को बिगाड़ना उचित नहीं होगा। इसलिए, इस महकमे द्वारा पहले जारी किए गए आदेश को संशोधित रूप में परिपालित किया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय के मामलों की निर्णयप्राप्तितके बाद स्थानीय सांस्कृत

इसलिए, इस महकमे द्वारा संशोधित रूप में जारी किए गए आपात आदेश को उच्च न्यायालय में मामलों के निर्णय होने तक क्रियाशील बनाए रखा जाना चाहिए, न केवल साम्प्रदायिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए बल्कि अधिनियम के अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी। [154– जी एच I; 155 –ए बी –]

एम इस्माइल फारूकी आदि बनाम. भारत संघ एवं अन्य, 119941 सप्लिमेंट। 5 एससीआर मैं, संदर्भित.

सिविल मूल क्षेत्राधिकार रिट याचिका (सी) संख्या 160/2002.

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।)

के.एन. रावल, सॉलिसिटर जनरल, और आर.एन. त्रिवेदी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ओ.पी. शर्मा, पी.एस. मिश्रा, कपिल सिब्बल, वाई.एच. मुछल्ला, डॉ. राजीव धवन, एस.एस. रे, सुश्री ननिता शर्मा, विवेक शर्मा, अभिषेक अत्रे, आमेर ई अहमद मदनी, आर.सी. गुबरेले. के.आर. गुप्ता, ए. मारियारपुथम, पी. परमेश्वरन, मनु शंकर मिश्रा, एस. चंद्रा शेखर, विष्णु शर्मा, आर.के. सिंह, सुश्री स्वरूपा रेड्डी, एम.एम. पांडे, रवि प्रकाश गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता, सुशेन्द्र कुमार चौहान, एस.एल. हर्ष, कीर्ति श्रीवास्तव, हुज़ेफ़ा अहमदी, इजाज़ मकबूल, नकुल दीवान, असलम अहमद, ब्रिजेश कलाप्पज़, अखिल सिब्बल, शकील अहमद, एम.ए. सिद्दीकी, टी.ए.

खान, मो. जेड.ए. खान, अब्दुल मुन्नान, जेड जिलानी, शफी अहमद खान, एस.ए. काशी, शकील अहमद सैयद, मो. तैयब खान, आर.सी. वर्मा, मुकेश वेन्ना, मनीष शंकर, अनीस सुहरावर्दी, सुश्री संध्या गोस्वामी, सुश्री हेमन्तिका वाही, त्रिपुरारी रे, विश्वजीत सिंह, क्रुनेश एस.पवार, रितेश अग्रवाल, रवि कुमार, डी.के. गर्ग और धर्म वीर सिंह रावल उपस्थित हुए दलों।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायमूर्ति राजेंद्र बाबू, द्वारा: विधेयक में उद्देश्यों और कारणों के विवरण में अंततः अयोध्या में कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण अधिनियम, 1993 [इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित] को अधिनियमित किया गया,

> " इसे इस प्रकार कहा गया है: "वहाँ एक रहा है अयोध्या में तत्कालीन राम जन्म भूमि–बाबरी मस्जिद ढांचे से संबंधित लंबे समय से चला आ रहा विवाद, जिसके कारण समय–समय पर सांप्रदायिक तनाव और हिंसा हुई और अंततः 6 दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचे का विनाश हुआ। सांप्रदायिक हिंसा फैल गई जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में मौतें, चोटें और संपत्ति का विनाश हुआ। इस विवाद ने देश में विभिन्न समुदायों के बीच सार्वजनिक व्यवस्था और सद्भाव के रखरखाव को प्रभावित किया है। चूंकि सांप्रदायिकता बनाए रखना आवश्यक है भारत के लोगों के बीच सद्भाव और आम भाईचारे की भावना को ध्यान में रखते हुए, एक परिसर की स्थापना के लिए विवादित ढांचे की जगह और उपयुक्त आसन्न भूमि का अधिग्रहण करना आवश्यक समझा गया, जिसे योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जा सके, जिसमें एक राम मंदिर और एक मस्जिद, सुविधाएं हों। तीर्थयात्रियों के लिए एक पुस्तकालय, संग्रहालय और अन्य उपयुक्त सुविधाएं स्थापित की जा सकती हैं।
>
> 2. xx xx xx
>
> 3. xx xx xx"
>
> अधिनियम की प्रस्तावना में भी, इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है: "अयोध्या में कुछ क्षेत्र के अधिग्रहण और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करने वाला एक अधिनियम।
>
> चूँकि, राम जन्म भूमि–बाबरी मस्जिद के रूप में जानी जाने वाली संरचना (इस तरह की संरचना के आंतरिक और बाहरी प्रांगणों के परिसर सहित) से संबंधित एक लंबे समय से विवाद रहा है, जो कि प्रागना हवेली में, अयोध्या के कोट रामचन्द्र गांव में स्थित है। अवध, उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद जिले की तहसील फैजाबाद सदर में;
>
> और जबकि उक्त विवाद ने देश में विभिन्न समुदायों के बीच सार्वजनिक व्यवस्था और सद्भाव के रखरखाव को प्रभावित किया है;
>
> और चूँकि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और भारत के लोगों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना आवश्यक है;

और जबकि उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से, अयोध्या में कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण करना आवश्यक है;

xxx xxx xxx"

एम.इस्माइल फारुकी आदि बनाम भारत संघ और अन्य में। , 1994 सप्लिमेंट। (5) एससीआर 1, अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने अधिनियम की योजना की जांच की और 3:2 के बहुमत से माना:

"1(ए) अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (3) वैकल्पिक विवाद प्रदान किए बिना सभी लंबित मुकदमों और कानूनी कार्यवाही को समाप्त कर देती है– पक्षों के बीच विवाद के समाधान के लिए समाधान तंत्र। यह विवाद के समाधान के लिए न्यायिक उपाय का विलुप्त होना है जो कानून के शासन को नकारने जैसा है। अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (3) इसलिए असंवैधानिक है और अमान्य।

(बी) अधिनियम के शेष प्रावधान हमारे द्वारा किए गए निर्माण पर किसी भी अमान्यता से ग्रस्त नहीं हैं अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) शेष अधिनियम से भिन्न है। तदनुसार, धारा 4 की उपधारा (3) को छोड़कर शेष अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती खारिज की जाती है।

(2) इस्लामिक देशों में लागू मुस्लिम कानून के तहत एक मस्जिद की स्थिति के बावजूद, धर्मनिरपेक्ष भारत में लागू मुस्लिम कानून के तहत एक मस्जिद की स्थिति किसी भी धर्म के पूजा स्थल के समान और उसके बराबर है; और इसे राज्य की संप्रभु या विशेषाधिकार शक्ति के प्रयोग में अधिग्रहण से अन्य धर्मों के पूजा स्थलों की तुलना में अधिक छूट प्राप्त नहीं है।

(3) विवादित क्षेत्र से संबंधित लंबित मुकदमे और अन्य कार्यवाही, जिसके भीतर संरचना [ऐसी संरचना के आंतरिक और बाहरी आंगनों के परिसर सहित], जिसे आमतौर पर राम जन्म भूमि–बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है, को निर्णय के लिए पुनर्जीवित किया जाएगा। उसमें विवाद का, अंतरिम आदेशों के साथ, उस सीमा को छोड़कर, जब अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों द्वारा अंतरिम आदेशों को संशोधित किया जाता है।

(4) अधिनियम की धारा 3 के आधार पर उक्त विवादित क्षेत्र को केंद्र सरकार में निहित करना, एक वैधानिक रिसीवर के रूप में, धारा 7 के अनुसार इसके प्रबंधन और प्रशासन के कर्तव्य के साथ सीमित है, जिसमें उप के तहत यथास्थिति बनाए रखने की आवश्यकता होती है। –अधिनियम की धारा 7 की धारा (2). वैधानिक रिसीवर के रूप में केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह मुकदमे में अंतिम निर्णय के कार्यान्वयन के लिए अधिनियम की धारा 6 के अनुसार विवादित क्षेत्र को सौंप दे। यही वह उद्देश्य है जिसके लिए विवादित क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया है।

(5) मुकदमों में आगे अंतरिम आदेश देने की अदालतों की शक्ति अधिनियम की धारा 7 के दायरे से बाहर के क्षेत्र तक सीमित और सीमित है।

(6) अधिनियम की धारा 3 के आधार पर अधिनियम द्वारा अर्जित विवादित क्षेत्र के अलावा निकटवर्ती क्षेत्र को केंद्र सरकार में निहित करना, उपधारा (1) के अनुसार प्रबंधन और प्रशासन की शक्ति के साथ पूर्ण है।) अधिनियम की धारा 7, जब तक कि यह अधिनियम की धारा 6 के अनुसार किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय या किसी ट्रस्ट के ट्रस्टियों में निहित न हो जाए। अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, विवादित क्षेत्र के अलावा निकटवर्ती क्षेत्र का आगे स्वामित्व, इसके अधिग्रहण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, समय पर और बताए गए तरीके से किया जाना चाहिए।

(7) अधिनियम की धारा 3 और धारा 6 में 'वेस्ट' शब्द का अर्थ अलग–अलग संदर्भों में समझा जाना चाहिए। (8) अधिनियम की धारा 8 पूरी तरह से केंद्र सरकार में निहित संपत्ति के मालिकों को मुआवजे के भुगतान के लिए है, जिसका स्वामित्व विवादित क्षेत्र से अधिक होने के कारण विवाद में नहीं है, जो अकेले विषय–वस्तु है। पुनर्जीवित सूट. यह विवादित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, जिसका स्वामित्व मुकदमों में तय किया जाना है और जिसके संबंध में केंद्र सरकार केवल सांविधिक रिसीवर है, जैसा कि संकेत दिया गया है, निर्णय के संदर्भ में इसे मालिक को बहाल करने का कर्तव्य है। सूट में.

(9) इस आधार पर निकटवर्ती क्षेत्र के किसी भी हिस्से के अधिग्रहण की चुनौती कि यह लंबे समय से चले आ रहे विवाद को निपटाने के कथित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनावश्यक है, इस स्तर पर जांच नहीं की जा सकती है, हालांकि, यह क्षेत्र सटीक रूप से अनावश्यक पाया गया है विवाद के निर्णय पर निर्धारित किए जाने वाले उद्देश्य के लिए आवश्यक क्षेत्र को निर्विवाद मालिकों को वापस किया जाना चाहिए। (10) विवादित क्षेत्र के आसपास कुछ धार्मिक संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए निर्विवाद मालिकों द्वारा चुनौती की अस्वीकृति, इस स्तर पर उन्हें अपनी चुनौती को नवीनीकृत करने की स्वतंत्रता दी गई है, यदि आवश्यक हो तो बाद में उचित चरण में, विवाद के निर्णय के लिए आवश्यक निर्धारित सटीक क्षेत्र से अधिक उनकी संपत्ति को केंद्र सरकार द्वारा अपने पास रखना।

(11) परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया 1993 का विशेष संदर्भ संख्या 1 अनावश्यक और अनावश्यक है और इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण से, हम बहुत सम्मानपूर्वक इसका उत्तर देने से इनकार करते हैं और इसे वापस कर देते हैं (12) उक्त अधिनियम की संवैधानिक वैधता और विशेष संदर्भ की रखरखाव से संबंधित प्रश्न इन शर्तों में तय किए जाते हैं।

इस कार्यवाही में, जिसे जनहित याचिका के रूप में शुरू किया गया है, कई राहतों का दावा किया गया था, लेकिन इच्छुक पार्टियों को पक्षकार बनाने और उनकी दलीलें सामने रखने के बाद जो स्पष्ट हो गया वह यह है कि किस तरह से आसन्न भूमि को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए (एसआईसी) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित स्वामित्व मुकदमे में निर्णय। इस न्यायालय ने 13.3.2002 को नियम जारी करते हुए निम्नलिखित आदेश दिया:

"...इस बीच, हम निर्देश देते हैं कि ग्राम कोट रामचन्द्र में राजस्व भूखंड संख्या 159 और 160 में स्थित 67.703 एकड़ भूमि पर जो केंद्र सरकार में निहित किसी भी व्यक्ति द्वारा भूमिपूजा या शिला पूजा सहित किसी भी प्रकार की कोई भी धार्मिक गतिविधि, चाहे वह प्रतीकात्मक हो या वास्तविक, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा उक्त भूमि का कोई भी हिस्सा सरकार द्वारा किसी को भी नहीं सौंपा जाएगा। इस रिट याचिका के निपटारे तक सरकार द्वारा अपने पास रखा जाएगा और न ही इस भूमि के किसी भी हिस्से को किसी धार्मिक उद्देश्य या उसके संबंध में कब्जा करने या उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

यह अगले आदेशों के अधीन है जो इस मामले में पारित किया जा सकता है।

उपरोक्त आदेश को एक अन्य आदेश दिनांक 14.3.2002 द्वारा निम्नलिखित शर्तों में स्पष्ट किया गया था:

"विद्वान अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद, चूंकि 13 मार्च, 2002 के हमारे आदेश के पैरा 3 में कुछ अस्पष्टता थी, इसलिए हम अपने आदेश के पैरा 3 को निम्नानुसार सही करते हैं।

इस बीच हम निर्देश देते हैं कि अयोध्या अधिनियम, 1993 में अधिग्रहण या केंद्रीय क्षेत्र की अनुसूची में वर्णित विभिन्न भूखंडों में स्थित 67703 एकड़ अधिग्रहित भूमि पर, जो केंद्र सरकार में निहित है, किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक गतिविधि न तो प्रतीकात्मक है और न ही भूमिपूजा या शिला पूजा सहित वास्तविक आयोजन की अनुमति दी जाएगी।"

इसके बाद दलील पूरी होने के बाद अंतरिम आदेश को रद्द करने और याचिका पर अंतिम सुनवाई की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया। अंतरिम आवेदन पर विचार करने के बजाय, हमने सोचा कि हमें मुख्य मामले का निपटारा करना चाहिए और इसलिए हमने अंततः मामले की सुनवाई की है।

वर्तमान मामले में दोनों पक्षों के विद्वान वकील एम.इस्माइल फारुकी के मामले [सुप्रा] के निर्णय पर बहुत अधिक निर्भर थे।

अधिनियम, जैसा कि संसद द्वारा पारित किया गया था, ने इस न्यायालय की राय प्राप्त करने और उक्त राय के संदर्भ में विवाद के निपटारे की आशा की। हालाँकि, इस न्यायालय में किया गया संदर्भ बिना किसी राय के राष्ट्रपति को वापस कर दिया गया है और अधिनियम की धारा 4(3) के प्रावधान जिसके द्वारा लंबित कार्यवाही समाप्त हो गई है, को अमान्य घोषित कर दिया गया है, मुकदमे और अन्य कार्यवाही साथ ही अंतरिम आदेशों को पुनर्जीवित कर दिया गया। इसलिए, अधिनियम के प्रावधानों की संपूर्ण धारणा उसी आलोक में बनानी होगी। जबकि याचिका का तर्क यह है कि एम.इस्माइल फारुकी के मामले में इस न्यायालय का निर्णय [सुप्रा] स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि आसन्न भूमि के अधिग्रहण का उद्देश्य विवादित भूमि के उचित उपभोग की आवश्यकता को पूरा करना है। इसका मालिक अंततः इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया जाना है और फैसले के दौरान इस न्यायालय द्वारा की गई विभिन्न टिप्पणियों पर विचार करना, विशेष रूप से अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक क्षेत्र की सीमा पर निर्भर करेगा विवादित भूमि के संबंध में मुसलमानों या हिंदुओं के पक्ष में निर्णय और संग्रहालय, पुस्तकालय और अन्य संरचनाओं से युक्त एक परिसर विकसित करने के उद्देश्य से तैयार की जाने वाली योजना पर। यह सब तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमों का निपटारा नहीं हो जाता। इसलिए, वे प्रार्थना करते हैं कि अंतरिम आदेश में

इस न्यायालय द्वारा आदेशित यथास्थिति को पूर्ण बनाया जाना चाहिए और उपरोक्त शर्तों में उचित राहत दी जानी चाहिए।

भारत संघ और अन्य का कहना है कि इस न्यायालय द्वारा पहले दी गई अंतरिम राहत एम. इस्माइल फारुकी के मामले [सुप्रा] में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के दायरे से परे है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को सीधे खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था और इस याचिका में किसी भी राहत देने के लिए शायद ही कोई उचित आधार रखा गया था। यह भी दलील दी गई है कि याचिका में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और इसमें न्यायालय के समक्ष उठाए गए विभिन्न तर्कों की सराहना करने के लिए आवश्यक विवरण शामिल नहीं हैं और याचिका में की गई कई प्रार्थनाएं पहले ही निरर्थक हो चुकी हैं।

कई अवसरों पर इस न्यायालय ने पत्रों, टेलीग्रामों या पोस्ट कार्डों या समाचार रिपोर्टों को रिट याचिका के रूप में माना है। ऐसी याचिकाओं में अलग–अलग पक्षों को नोटिस के बाद मामले में सामने आने वाली दलीलों के आधार पर राहत दी गई है या इनकार किया गया है. इसलिए, यह न्यायालय उन मामलों पर विचार नहीं करेगा जहां सार्वजनिक हित तकनीकी या संकीर्ण तरीके से शामिल हो। विशेष रूप से, जब इस न्यायालय ने इस याचिका पर विचार किया है, विभिन्न पक्षों को नोटिस जारी किया है, नए पक्षों को पक्षकार बनाया है और अंतरिम आदेश भी दिया है, तो इस आधार पर याचिका का निपटारा करना इस न्यायालय के लिए उचित नहीं होगा।

. इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करना या उसका ख़ारिज होना इस याचिका पर विचार करने में आड़े नहीं आएगा। उच्च न्यायालय में दायर उस रिट याचिका का दायरा वर्तमान कार्यवाही में किए गए आग्रह से भिन्न है जो अर्जित भूमि के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमों के लंबित रहने के दौरान यथास्थिति बनाए रखने तक सीमित है।

अधिनियम की प्रस्तावना से ही पता चलता है कि अधिनियम का उद्देश्य देश में विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। यदि अधिग्रहण न केवल विवादित भूमि का, बल्कि निकटवर्ती भूमि का भी उस आधार पर किया गया है, तो यह सूत्र पूरी कार्यवाही के दौरान चलेगा और हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब विवाद अभी तक हल नहीं हुआ है, तो सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना और शांति की नितांत आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब जुनून चरम पर होता है, तो निकटवर्ती भूमि में होने वाली कई प्रकार की गतिविधियों की मांग की जाती है। यदि न्यायालय के समक्ष लंबित विवाद के समाधान से पहले भी ऐसी भूमि पर ऐसी कोई गतिविधि की जाती है, तो यह इतने लंबे समय से कायम सद्भाव और शांति को प्रभावित कर सकता है।

अधिनियम की धारा 6(1) केंद्र सरकार को अपने अधिकार, स्वामित्व और हित या उनमें से किसी भी क्षेत्र या उसके किसी हिस्से को किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय या ट्रस्ट को ऐसे नियमों और शर्तों पर स्थानांतरित करने में सक्षम बनाती है। उसी को बरकरार रखने के बजाय थोपना उचित समझें। धारा 6(2) और (3) केंद्र सरकार द्वारा वैधानिक हस्तांतरण की कुछ व्यवस्थाओं का प्रावधान करती है, जिसमें यह घोषणा की जाती है कि स्थानांतरित व्यक्ति प्रश्न में क्षेत्र में समान अधिकार और हित प्राप्त करके सरकार के स्थान पर कदम रखेगा। यह भी कि धारा 4, 5, 7, 11, जहां तक संभव हो, ऐसे स्थानांतरित व्यक्ति पर वैसे ही लागू होंगे जैसे केंद्र सरकार पर लागू होते हैं।

एम. इस्माइल फारुगुई के मामले [सुप्रा] में चर्चा के दौरान, यह इस प्रकार देखा गया है:

तथ्यों का वर्णन यह दर्शाता है कि अधिनियम के तहत संपत्तियों का अधिग्रहण केवल मुस्लिम समुदाय के ही नहीं बल्कि दोनों समुदायों के अधिकारों को प्रभावित करता है। मुसलमानों द्वारा दावा किया गया हित केवल उस विवादित स्थल पर है जहां मस्जिद विध्वंस से पहले खड़ी थी। इस दावे पर हिंदुओं की आपत्ति पर फैसला होना है. अधिनियम के तहत अर्जित शेष संपूर्ण संपत्ति ऐसी है जिस पर मुसलमानों द्वारा किसी स्वामित्व का दावा नहीं किया गया है। इसका एक बड़ा हिस्सा हिंदुओं की संपत्तियों का है, जिनके मालिकाना हक पर विवाद भी नहीं है। संपत्ति सहित बड़े क्षेत्र के अधिग्रहण के लिए दिया गया औचित्य, जिसका स्वामित्व विवादित नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि निर्णय के अंतिम परिणाम को आसपास के क्षेत्र में हिंदुओं से संबंधित संपत्तियों के अस्तित्व के कारण अर्थहीन नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि विवादित ढांचे पर मुसलमानों का अधिकार पाया जाता है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि विवादित ढांचे को मुस्लिम समुदाय को सौंपने की आवश्यकता वाले विवाद के फैसले में मुसलमानों के सफल होने की स्थिति में उनकी सफलता को विवादित क्षेत्र में उचित पहुंच और अधिकारों के आनंद से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। निकटवर्ती संपत्तियों के हिंदू मालिकों के स्वामित्व के अधिकारों का प्रयोग। जाहिर है, यही कारण है कि सफल पक्ष को उसका वह हिस्सा उपलब्ध कराने के लिए निकटवर्ती क्षेत्र का भी अधिग्रहण किया गया है, जो निर्णय के अंतिम परिणाम पर सफलता के फल का उचित आनंद लेने के लिए आवश्यक माना जाता है। यह स्पष्ट है कि आसन्न संपत्तियों के अधिग्रहण का एक उद्देश्य मुकदमेबाजी में सफलता की स्थिति में मुस्लिम समुदाय द्वारा विवादित स्थल के प्रभावी आनंद को सुनिश्चित करना है और आसन्न क्षेत्र का अधिग्रहण मुख्य के लिए आकस्मिक है। उद्देश्य और इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। "मानस भवन" और "सीता की रसोई", दोनों हिंदुओं से संबंधित हैं, ऐसी इमारतें हैं जो विवादित स्थल को करीब से देखती हैं और उनका अधिग्रहण कर लिया गया है क्योंकि वे विवादित क्षेत्र के संबंध में रणनीतिक स्थान पर हैं। विवादित संरचना क्षेत्र, जो अपने आप में एक अद्वितीय वर्ग बनाता है, के निकट होने के कारण निकटवर्ती मंदिरों या धार्मिक इमारतों को प्राप्त करने की आवश्यकता स्वीकार्य है (एम. पद्मनाभ अयंगर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अखाड़ा श्री ब्रह्म बूटा बनाम पंजाब राज्य देखें)) हम इन निर्णयों में बताए गए सिद्धांत को स्वीकार करते हैं क्योंकि यह एक बड़े उद्देश्य को पूरा करता है।

xxx xxx xxx

हालाँकि, बाद के चरण में जब अधिग्रहण के घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सटीक अधिग्रहीत क्षेत्र निर्धारित किया जा सकता है, तो यह न केवल स्वीकार्य होगा, बल्कि वांछनीय भी होगा कि अतिरिक्त अतिरिक्त क्षेत्र को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया जाए और उसे वापस कर दिया जाए। पहले का मालिक. विवादित क्षेत्र से संबंधित विवाद को सुलझाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनावश्यक होने के आधार पर निकटवर्ती क्षेत्र के किसी भी हिस्से के अधिग्रहण की चुनौती की इस स्तर पर जांच नहीं की जा सकती है, लेकिन यदि अतिरिक्त क्षेत्र उसके मालिक को वापस नहीं किया जाता है इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सटीक क्षेत्र अंततः निर्धारित होने के बाद भी। ऐसी किसी भी संपत्ति के मालिक के लिए यह खुला होगा कि वह अधिग्रहण के उद्देश्य से संबंधित अनावश्यक अधिग्रहण को चुनौती दे। विवादित क्षेत्र के आसपास स्थित ऐसी किसी भी संपत्ति के निर्विवाद मालिकों द्वारा इस स्तर पर अधिग्रहण की चुनौती को अस्वीकार करना उनके लिए इस स्वतंत्रता के आरक्षण के साथ है। उनके

दावे का कोई मुकाबला नहीं है या केंद्र सरकार को छोड़कर किसी अन्य द्वारा आसन्न संपत्तियों के अधिग्रहण को रद्द नहीं किया जा सकता है, जो आवश्यकता के आधार पर अधिग्रहण को उचित ठहराना चाहता है। हमारे द्वारा बनाए गए क़ानून के निर्माण पर, यह ऐसी आसन्न संपत्तियों के संबंध में तार्किक, उचित और उचित दृष्टिकोण प्रतीत होता है जिसमें निर्विवाद मालिक के अलावा कोई भी स्वामित्व और हित का दावा नहीं करता है।

xxx xxx xxx

हिंदुओं के निकटवर्ती अविवादित क्षेत्र के अधिग्रहण पर इस आधार पर हमला किया गया है कि यह अनावश्यक था क्योंकि इसका स्वामित्व निर्विवाद है। विवादित क्षेत्र से सटे बड़े क्षेत्र के अधिग्रहण का कारण बताया गया है. इसलिए, यह उस विवाद के समाधान से असंबंधित नहीं है जो पूरे अधिग्रहण का कारण है। हालाँकि, प्रथम दृष्टया, निकटवर्ती क्षेत्र का अधिग्रहण जिसके संबंध में स्वामित्व का कोई विवाद नहीं है और जो हिंदुओं का है, हिंदुओं के खिलाफ एक झुकाव प्रतीत हो सकता है, फिर भी बारीकी से जांच करने पर ऐसा नहीं है क्योंकि यह उनके लिए है सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने और बढ़ावा देने और धर्मनिरपेक्षता के पंथ के अनुरूप होने का बड़ा राष्ट्रीय उद्देश्य। एक बार जब यह पाया जाता है कि विवादित क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र का अधिग्रहण करने की अनुमति है, तो विवादित क्षेत्र के अधिग्रहण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए और पक्षों के बीच अंतिम न्यायनिर्णयन के परिणाम को लागू करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि विवाद में मुस्लिम समुदाय की सफलता की स्थिति उनकी सफलता सार्थक बनी हुई है, आसन्न की सीमा को नीति के क्षेत्र में आवश्यक माना जाता है और यह न्यायिक जांच का मामला नहीं है या अधिनियम की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने का आधार नहीं है। हालाँकि, यह केंद्र सरकार के कर्तव्य की चेतावनी के साथ है कि वह इसे उसके मालिक को लौटा दे, जैसा कि पहले बताया गया है, अगर बाद में यह अनावश्यक पाया जाता है, और कुल आवश्यकता निर्धारित होने पर अनावश्यक अधिग्रहण को चुनौती देने के लिए मालिक को स्वतंत्रता का आरक्षण दिया जाता है। ।"

ऊपर उद्धृत टिप्पणियों से, यह स्पष्ट है कि निकटवर्ती भूमि, हालांकि केंद्र सरकार में निहित है, विवादित संपत्ति के संबंध में मुकदमे के नतीजे के आधार पर अलग–अलग तरीकों से उपयोग करना होगा। इस प्रकार निकटवर्ती भूमि का उपयोग किस प्रकार या किस सीमा तक किया जा सकता है, यह उच्च न्यायालय में लंबित विवाद के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा। बड़ी भूमि का अधिग्रहण मुख्य उद्देश्य के लिए आकस्मिक है। इस प्रकार, दो अधिग्रहीत भूमि आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और अंतराल के दौरान अलग–अलग उपचार के लिए कार्यवाही के इस चरण में अलग नहीं की जा सकती हैं। इसके अलावा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई भूमि अनावश्यक हो जाती है तो ऐसी भूमि मालिक को वापस करनी होगी, जिसे अधिग्रहण की वैधता को चुनौती देने के लिए उचित कार्यवाही शुरू करनी होगी जैसा कि एम में इस न्यायालय के फैसले के दौरान दर्शाया गया है। .इस्माइल फारूकी का मामला [सुप्रा]। यदि इस स्तर पर अधिनियम की धारा 6 के तहत भूमि किसी अन्य निकाय या ट्रस्ट को हस्तांतरित की जाती है तो आगे जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए, मुकदमों के अंतिम निपटारे तक यथास्थिति बनाए रखनी होगी। हमारा मानना है कि इस न्यायालय के पहले दिए गए आदेश एम. इस्माइल फारुकी के मामले में निर्णय के दायरे से बाहर नहीं हैं।

सबसे ऊपर, 1992 के बाद से यथास्थिति बनाए रखी गई है और आवेदन के दौरान निर्धारित की गई कोई भी गतिविधि अब तक करने की आवश्यकता नहीं है। जब लंबे समय से एक विशेष स्थिति बनी हुई है – जैसा कि वर्तमान मामले में एक दशक से अधिक समय से है – और जब उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विवादों का निर्णय अंतिम चरण में पहुंच रहा है, तो परेशान करना उचित नहीं होगा वह स्थिति. यह सर्वविदित है कि अदालतों के समक्ष कार्यवाही की समाप्ति पर पार्टियों को उचित राहत देने के लिए संपत्ति को उसकी मूल स्थिति में संरक्षित करना नितांत आवश्यक है और इसलिए, हमें नहीं लगता कि यह उन मामलों में से एक है जिसमें यह उस अवस्था को अशांत करना आवश्यक हो जाता है।

पूरे मामले पर विचार करने पर, हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा 13.3.2002 को दिया गया आदेश, जैसा कि 14.3.2002 को दिए गए आदेश द्वारा संशोधित किया गया है, उच्च न्यायालय में मुकदमों के निपटान तक प्रभावी रहना चाहिए। न केवल सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना बल्कि अधिनियम के अन्य उद्देश्यों को भी पूरा करना इलाहाबाद. रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाएगा।

मामले को समाप्त करने से पहले, हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं कि सभी विद्वान वकील और पक्ष जो मामले पर पूरी तरह से बहस करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे, उन्होंने न्यायालय में लाए बिना मामले में उत्पन्न होने वाले तथ्यों और कानून के आधार पर ही अपने–अपने मामले प्रस्तुत किए हैं। चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक, किसी भी तरह का जुनून बाहर भड़क रहा है। हम न्यायालय में अधिवक्ताओं और पक्षकारों के इस रुख की बहुत सराहना करते हैं।

याचिका निस्तारित की गई।